लेफ्टिनेंट गवर्नर, एन.सी.टी. और अन्य

बनाम

वेद प्रकाश उर्फ वेदु

5 मई, 2006

[एस.बी. सिन्हा और पी.के. बालासुब्रमण्यन, जे.जे.]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978-धारा 47, 48 और 50- निर्वासन के आदेश-रिट याचिका दायर करके आदेश को चुनौती देने वाली कार्यवाही- अदालतों द्वारा हस्तक्षेप- दायरा-माना, आदेश के द्वारा वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिमाग के प्रयोग को प्रदर्शित करना चाहिए और यह सामग्री पर आधारित होना चाहिए-अधिकारी की संतुष्टि, हालांकि व्यक्तिपरक है, वस्तुनिष्ठता पर आधारित होनी चाहिए-सामग्री की पर्याप्तता या किसी अन्य दृष्टिकोण की संभावना हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती है- अदालत खुद को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड की जांच कर सकती है कि सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है और यह भी कि गवाहों ने गवाही देने के बारे में आशंकाओं का खुलासा किया है कार्यवाहक की गतिविधियों के कारण अदालत में- अदालत ने गवाहों के नाम या ऐसे मामलों के विवरण का खुलासा करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश नहीं

दिया है- तथ्यों में, निर्वासन का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है और इसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले स्थापित किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47 के संदर्भ में प्रतिवादी के खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही इस आधार पर शुरू की कि उसकी गतिविधियों और कृत्यों से व्यक्ति और संपत्ति को चिंता, खतरा और नुकसान हो रहा था और पहले के नोटिस की निरंतरता में एक पूरक नोटिस भी जारी किया गया था। 1978 अधिनियम की धारा 50 के तहत 13.04.2004 से दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से परे हटाने का निर्देश देते हुए प्रतिवादी के खिलाफ निर्वासन का आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर करके निर्वासन के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इस आधार पर निर्वासन के आदेश को रद्द कर दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि कारण बताओ नोटिस में उन गवाहों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था जिनके बारे में कहा गया था कि वे उसके अनिच्छुक थे या प्रतिवादी के डर के कारण खिलाफ गवाही देने आगे नहीं आए थे। अपीलकर्ताओं ने उन मामलों का भी खुलासा नहीं किया जिनमें गवाहों ने डर के कारण या धमकी आदि के कारण प्रतिवादी के खिलाफ गवाही नहीं दी थी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

1. क्षेत्र में कार्यरत कानून अब बिल्कुल नया या अछूता (रेस इंटीग्रा) नहीं है, जिस पर इसके बाद ध्यान दिया जा सकता है:

(i) अधिनियम के तहत कार्यवाही में सभी वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए एक निष्कासन कार्यवाही व उसके उद्देश्य की तुलना निवारक निरोध मामले से नहीं की जा सकती।

(iii) निर्वासन का आदेश पारित होने से पहले, कार्यवाहक सुनवाई के अवसर का हकदार है।

(iv) अधिनियम में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

(v) प्राधिकारी की संतुष्टि उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए।

(vi) दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 47 के तहत एक कार्यवाही इस अर्थ में सामान्य कार्यवाही से अलग स्तर पर है कि उत्तरार्ध में साक्ष्य के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है, जिससे कार्यवाहक प्राप्तकर्ता को उनसे निपटने का अवसर मिलता है तथा पूर्व वाली में सामान्य आरोप उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। [939-ए-ई]

2. निर्वासन का आदेश हमेशा बाहरी व्यक्ति की अवैध गतिविधियों के क्षेत्र तक ही सीमित होना चाहिए। कार्यकारी आदेश में वैधानिक प्राधिकारी की ओर से उचित विवेक का प्रदर्शन होना चाहिए। जब किसी आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जाता है तो वह सामग्री देखी जाएगी, जिस पर प्राधिकारी की संतुष्टि आधारित है। प्राधिकारी की संतुष्टि हालांकि मुख्य रूप से व्यक्तिपरक है, लेकिन वस्तुनिष्ठता पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन सामग्री की पर्याप्तता पर रिट अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि विवादित आदेश पारित करने में प्राधिकरण प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा है या अप्रासंगिक कारकों पर अपना निर्णय आधारित किया है। केवल दूसरे दृष्टिकोण की संभावना ही हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती। यह ऐसा मामला नहीं है जहां तीसरे अपीलकर्ता के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया था। [939-ए-सी]

दिल्ली के एनसीटी राज्य और अन्य बनाम संजीव उर्फ बिट्टू, [2005] 5 एससीसी 181 और गाजी सादुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2003]7 एससीसी 330, पर भरोसा किया।

3.1 उच्च न्यायालय और यह न्यायालय निस्संदेह एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की ईर्ष्यापूर्वक रक्षा करेंगे। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अदालतें कार्यवाही करने वाले व्यक्ति के मानवाधिकार को बनाए

रखने के लिए सभी प्रयास करेंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार की निस्संदेह रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन किसी कानून के मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या करते समय और क्षेत्र में चल रहे उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, अदालत स्वयं रिकॉर्ड की जांच कर सकती है, ताकि न केवल इस उद्देश्य के लिए अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके कि कार्यवाही करने वाले के लिए उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान किया गया है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए भी कि गवाहों ने कार्यवाहीकर्ता की गतिविधियों के कारण अदालत में सच्चाई और निडरता से गवाही देने के बारे में अपनी आशंकाओं का खुलासा किया है। एक बार इस तरह की संतुष्टि हो जाने पर, उच्च न्यायालय आम तौर पर निर्वासन के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत, किसी भी स्थिति में, अधिकारियों को गवाहों के नाम या उन मामलों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश नहीं देगी, जहां ऐसे गवाहों से केवल इस कारण से पूछताछ की गई थी कि इससे उन्हें और अधिक नुकसान हो सकता है। [1939-सी-एफ]

पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर बनाम उप. पुलिस आयुक्त, राज्य महाराष्ट्र का, एआईआर (1973) एससी 630, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सलेम हसन खान, एआईआर (1989) एससी 1304 और गाजी सदुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2003] 7 एससीसी 330, पर भरोसा किया गया।

3.2 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं था कि तीसरा अपीलकर्ता उन मामलों का खुलासा करने के लिए बाध्य था, जिनमें गवाहों ने डर के कारण या धमकी आदि के कारण प्रतिवादी के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। यदि मामलों को संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कार्यवाहक करने वाले की गतिविधियों के कारण गवाह सामने नहीं आ रहे थे, यह आवश्यक गोपनीयता का उल्लंघन होगा और उस उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47 को अधिनियमित किया गया था। [938-जी-एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 530/2006

उच्च न्यायालय दिल्ली के आपराधिक रिट याचिका संख्या 442/2004 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 04.04.2005 से।

अपीलकर्ता की ओर से मुक्ता गुप्ता, टीए खान और अनिल कटियार।

प्रतिवादी की ओर से हरजिंदर सिंह, वंदना शर्मा और एसवी देशपांडे।

न्यायालय का निर्णय **एस.बी. सिन्हा, जे.** द्वारा दिया गया

लीव मंजूर।

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47 के संदर्भ में प्रतिवादी के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी। उक्त कार्यवाही अन्य

बातों के साथ- साथ इस आधार पर शुरू की गई थी कि उसकी गतिविधियों और कृत्यों से लोगों को खतरा, खतरा और नुकसान हो रहा था। संपत्ति।

यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी:

क्र.सं.	एफआईआर नंबर	दिनांक	कानूनी धारा	पुलिस थाना
1.	124	29.04.82	308/34 भा.दं.सं.	कल्याण पुरी
2.	123	02.03.84	452/324/34 भा.दं.सं.	कल्याण पुरी
3.	469	08.11.85	308/506/427/323/34 भा.दं.सं.	कल्याण पुरी
4.	73	19.02.91	307/506/34 भा.दं.सं.	कल्याण पुरी
5.	15	09.01.93	147/148/149/323 भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी
6.	480	10.08.93	304-A भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी

7.	4	05.01.99	452/342/323/354/427/34 भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी
8.	309	11.09.99	354/509/323/506/34 भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी
9.	310	12.09.09	452/308/34 भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी
10.	396	29.10.01	458/323/427/506 भा.दं.सं.	त्रिलोक पुरी

जबकि प्रतिवादी को क्रम संख्या 4 और 9 में वर्णित उदाहरणों और /या प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में दोषी ठहराया गया था, अन्य मामलों में, धारा संख्या 1 और 10 के तहत वर्णित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में उसे बरी कर दिया गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा क्रमशः 308/34 एवं 458/323/427/506 जो अभी भी लम्बित बतायी जाती है।

प्रतिवादी को जारी कारण बताओ नोटिस में यह आरोप लगाया गया था:

> "यह कि आपके आवाजाही और कृत्यों से व्यक्ति या संपत्ति को खतरा, खतरा पैदा हो सकता है। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आप अध्याय XVI, XVII, XXII या

आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध में शामिल हैं या शामिल होने की संभावना है। क्या यह सच है कि आप किसी एक अकेली घटना में शामिल नहीं थे, बल्कि 1982 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और खतरनाक थे, जिससे आपका दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से में रहना समुदाय के लिए खतरनाक था।

यह कि गवाह अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में आशंका के कारण सार्वजनिक रूप से आपके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। यह मानने के उचित आधार हैं कि ऊपर पैरा (i) में दिये गये अपराधों जैसे अपराध में शामिल हो सकते हैं।

आपसे यह समझाने के लिए कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार आपके खिलाफ दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से बाहर निर्वासन का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए।"

प्रतिवादी ने कारण बताओ दायर किया। उन्होंने अपनी ओर से गवाहों से भी पूछताछ की। उनके मुताबिक उन्हें कई झूठे मामलों में फंसाया गया है, चूंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उसके भाई के प्रति शत्रुतापूर्ण थे,

इसलिए उन्होंने उसे बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के कई झूठे मामलों में फंसा दिया था।

31.12.2003 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा एक पूरक नोटिस जारी किया गया था, जिसे पिछले नोटिस दिनांक 7.8.2003 की निरंतरता में दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किया गया था।

07.04.2004 को या इसके आसपास प्रतिवादी के खिलाफ निष्कासन का एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उसे 13.04.2004 से दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा से बाहर हटाने का निर्देश दिया गया था।

बार में उठाए गए विवादों को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में, हम दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 47, 48 और 50 को पढ़ सकते हैं:

47. अपराध करने वाले व्यक्तियों को हटाया जाना- जब भी यह पुलिस आयुक्त को दिखाई देता है-

(ए) कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कृ त्यों से व्यक्ति या संपत्ति को खतरा, खतरा या नुकसान हो रहा है या होने वाला है; या

(बी) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा से जुड़े अपराध या अध्याय XII, अध्याय XVI, अध्याय XVII या अध्याय XXII के तहत दंडनीय अपराध में लगा हुआ है या शामिल होने

वाला है। दंड संहिता या उस संहिता की धारा 290 या धारा 489 ए से 489 ई (दोनों सम्मिलित) के तहत या ऐसे किसी अपराध के लिए उकसाने में; या

(सी) कि ऐसा व्यक्ति-

(i) इतना हताश और खतरनाक है कि उसका दिल्ली में या उसके किसी भी हिस्से में बड़े पैमाने पर रहना समुदाय के लिए खतरनाक हो गया है; या

(ii) हिंसा के कृत्यों या बल प्रदर्शन द्वारा अन्य व्यक्तियों को आदतन डराते हुए पाया गया है; या

(iii) आदतन झगड़ा या शांति भंग या दंगा करता है, या आदतन चंदा की जबरन वसूली करता है या अपने लिए या दूसरों के लिए अवैध आर्थिक लाभ के लिए लोगों को धमकी देता है; या

(iv) आदतन महिलाओं और लड़कियों पर अशोभनीय टिप्पणियाँ करता रहा है, या उन्हें छेड़छाड़ करता रहा है; और पुलिस आयुक्त की राय में गवाह अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में आशंका के कारण ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं, पुलिस आयुक्त आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को विधिवत रूप से लिखित रूप में, या ढोल बजाकर या अन्यथा जैसा वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसा आचरण करने का निर्देश देगा जो हिंसा

और अलार्म को रोकने या खुद को दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से से बाहर निकालने के लिए आवश्यक लगे। ऐसे मार्ग पर और ऐसे समय के भीतर जो पुलिस आयुक्त निर्दिष्ट कर सकते हैं और दिल्ली या उसके उस हिस्से में प्रवेश या वापसी नहीं करेंगे, जैसा भी मामला हो, जहां से उन् हें खुद को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था।

स्पष्टीकरण- एक व्यक्ति जो इस धारा के तहत कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले एक वर्ष के भीतर की अवधि के दौरान कम से कम तीन मौकों पर इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करता हुआ या उसमें शामिल पाया गया हो, उसे दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उसने यह कृत्य आदतन किया है।

48. कुछ अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को हटाया जाना- यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है-

(ए) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII, अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत अपराध; या

(बी) दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1955 की धारा 3 या धारा 4 के तहत अपराध, या उस अधिनियम की धारा 12 के तहत जहां तक यह सट्टा जुए से संबंधित है या किसी अन्य प्रावधान के तहत दो या दो से अधिक अवसरों पर वह अधिनियम (उस अधिनियम की धारा 12 सहित जहां तक यह सट्टा जुए से संबंधित नहीं है); या

(सी) महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी अपराध का; या

(डी) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 29 के तहत किसी भी

अपराध के लिए; या

(ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत किसी भी अपराध के लिए; या

(च) दिल्ली में लागू पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 61, धारा 63 या धारा 66 के भी अपराध के लिए; या

(छ) किसी अपराध के तहत किसी दो या दो से अधिक अवसरों पर-

(i) अफ़ीम अधिनियम, 1878; या

(ii) खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930; या

(iii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; या

(iv) दिल्ली में लागू बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 की धारा 11; या

(ज) इस अधिनियम की धारा 105 या धारा 107 के तहत अपराध के तीन या अधिक अवसरों पर, पुलिस आयुक्त, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति इस धारा में निर्दिष्ट किसी भी

अपराध के कमीशन में फिर से शामिल होने की संभावना है, तो लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को खुद को सीमा से परे हटाने का निर्देश दे सकता है। दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से में, ऐसे मार्ग से और ऐसे समय के भीतर जो पुलिस आयुक्त निर्दिष्ट कर सकते हैं और दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से में, जैसा भी मामला हो, प्रवेश नहीं करेगा या वापस नहीं आएगा, जहां से उसे खुद को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था।

50. धारा 46, 47 या 48 के तहत आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की जाएगी-

(1) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धारा 46, धारा 47 या धारा 48 के तहत आदेश देने से पहले, पुलिस आयुक्त लिखित नोटिस द्वारा उसे उसके खिलाफ लगाए गए भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृ ति के बारे में सूचित करेगा और उसे उचित अवसर देगा। उनके संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना। यदि ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी गवाह की जांच के लिए आवेदन करता है, तो पुलिस आयुक्त ऐसे आवेदन को स्वीकार कर लेगा और ऐसे गवाह की जांच करेगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के बारे में पुलिस आयुक्त की राय न हो। ऐसा आवेदन परेशान करने या देरी करने के उद्देश्य से किया गया है।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी गवाह की जांच के लिए आवेदन करता है, तो पुलिस आयुक्त ऐसे आवेदन को

स्वीकार कर लेगा और ऐसे गवाह की जांच करेगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के बारे में पुलिस आयुक्त की राय न हो। ऐसा आवेदन परेशान करने या देरी करने के उद्देश्य से किया गया है।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी लिखित स्पष्टीकरण मामले के रिकॉर्ड के साथ दर्ज किया जाएगा।

(4) ऐसा व्यक्ति एक वकील द्वारा पुलिस आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

(5) (ए) पुलिस आयुक्त किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिसके खिलाफ धारा 46, धारा 47 या धारा 48 के तहत कोई आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, ऐसे व्यक्ति से लिखित आदेश द्वारा मांग कर सकता है। उसके सामने उपस्थित हों और पूछताछ के दौरान उपस्थिति के लिए जमानतदारों के साथ या उसके बिना एक सुरक्षा बांड प्रस्तुत करें।

(बी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 119 से 124 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, सुरक्षा बांड प्रस्तुत करने के खंड (ए) के तहत आदेश के संबंध में लागू होंगे।

(6) पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, पुलिस आयुक्त, उप- धारा (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है और संहिता की

धारा 70 से 89 (दोनों सम्मिलित) के प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, जहां तक संभव हो, ऐसे वारंट के संबंध में लागू होगी।

(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 445, धारा 446, धारा 447 या धारा 448 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा के तहत निष्पादित सभी बांडों के संबंध में लागू होंगे।

अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 3 की दिनांक 7 अगस्त, 2003 की नोटिंग /कार्यवाही में विचार किया गया था, जो इस प्रकार है:

वेद प्रकाश उर्फ वेदु पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी एस- 4, पांडव नगर, दिल्ली के खिलाफ गवाही देने के लिए दो सार्वजनिक गवाह तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/पूर्व श्री वीवी चौधरी के समक्ष पेश हुए। कैमरे पर बयान दर्ज किए गए। मेरे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर और एसीपी कल्याण पुरी और एसएचओ /पांडव नगर के साथ उस पर चर्चा करने के बाद और कैमरे के गवाहों के बयान देखने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि प्रतिवादी के खिलाफ धारा 47 डीपी अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 45 के बराबर हैं। बॉम्बे पुलिस अधिनियम के उक्त प्रावधान की व्याख्या इस न्यायालय की एक

पीठ के समक्ष विचार के लिए आई पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर बनाम उप.कॉमरेड पुलिस विभाग,महाराष्ट्र राज्य, एआईआर (1973) एससी 630, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क उठाए गए:

(iii) बाहरी प्राधिकारी को एक तर्क संगत आदेश पारित करना होगा अन्यथा अपील का अधिकार भ्रामक हो जाएगा।

(iv) राज्य सरकार को अपील खारिज करने के आदेश के समर्थन में कारण भी बताने चाहिए थे। कारण बताने में इसकी विफलता दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाती है;

चंद्रचूड़, जे., जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, ने कहा:

... धारा 56 के खंड (ए) या (बी) के तहत निर्वासन का आदेश पारित किया जा सकता है, और के वल तभी, जब संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट हो कि गवाह प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में उनकी ओर से आशंका किसी खुले अभियोजन में अपेक्षित विवरणों का पूर्ण और संपूर्ण खुलासा निष्कासन कार्यवाही के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। यदि कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति को घटनाओं की विशिष्ट तिथियों या उन घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के नाम

जैसे ठोस डेटा प्रस्तुत करने के लिए होता, तो उन लोगों की पहचान तय करना काफी आसान होता जो अपने व्यक्ति को चोट लगने केडर से बाहर निकलते हैं या संपत्ति सार्वजनिक रूप से बयान देने को तैयार नहीं हैं। समाज में अराजक तत्वों का एक समूह है, जिसे न्यायिक परीक्षण के स्थापित तरीकों से सजा दिलाना असंभव है क्योंकि ऐसे परीक्षणों में कानूनी सबूत के बिना कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है और कानूनी साक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि प्रतिशोध के डर से गवाह सार्वजनिक रूप से गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। यह बताता है कि क्यों अधिनियम की धारा 59 अधिकारियों पर प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति को" उसके खिलाफ भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति के बारे में सूचित करने" के लिए एक सीमित दायित्व लगाती है। वह दायित्व प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति के सह-सापेक्ष अधिकार की सीमा तय करता है। धारा 56 के तहत निर्वासन का आदेश पारित होने से पहले, वह अपने खिलाफ लगाए गए भौतिक आरोपों और उन आरोपों की सामान्य प्रकृति को जानने का हकदार है। वह भौतिक आरोपों से संबंधित विशिष्ट विवरणों के बारे में सूचित होने का हकदार नहीं है।

कोर्ट अपने पहले के फैसले का जिक्र कर रहा हैहरि खेमू गवली बनाम पुलिस उपायुक्त, बॉम्बे और अन्य, [1956] एससीआर 506 और गुजरात राज्य और अन्य आदि बनाम मेहबूब खान उस्मान खान [1968] 3 एससीआर 746। इस तर्क को खारिज कर दिया कि बाहरी व्यक्ति के

खिलाफ जारी किया गया नोटिस अस्पष्ट था। बिंदु (iii) और (iv) के संबंध में, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, यह कहा गया था:

14. तीसरे और चौथे बिंदु का वही उत्तर है जो दूसरे बिंदु का है जिस पर हमने अभी चर्चा की है। सटीक रूप से उन कारणों के लिए जिनके लिए प्रस्तावित बाहरी के वल भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति के बारे में सूचित होने का हकदार है, अपील में न तो बाहरी प्राधिकारी और न ही राज्य सरकार को निर्णय की प्रकृति में एक तर्क संगत आदेश लिखने के लिए कहा जा सकता है। यदि उन अधिकारियों को मामले में सबूतों पर चर्चा करनी होती, तो उन गवाहों की पहचान तय करना आसान होता जो प्रस्तावित निर्वासन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं। बाहरी व्यक्ति के खिलाफ सबूतों की चर्चा वाला एक तर्क संगत आदेश संभवतः अत्याचार और उत्पीड़न का एक और दौर शुरू कर देगा।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सलेम हसन खान एआईआर (1989) एससी 1304, इस न्यायालय ने पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर (सुप्रा) के आदेश का पालन किया।

दिल्ली के एनसीटी राज्य और अन्य बनाम संजीव @ बिट्टू, [2005] 5 एससीसी 181, इस न्यायालय ने फिर से कहा:

25. जैसा कि गाजी सदुद्दीन मामले में देखा गया है, प्राधिकारी की संतुष्टि में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि दर्ज की गई संतुष्टि बिना किसी सबूत के, सबूतों की गलत व्याख्या के आधार पर प्रदर्शनात्मक रूप से विकृत है या जिसे एक उचित व्यक्ति नहीं बना सकता है या संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह में उस सीमा तक, प्राधिकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि में वस्तुनिष्ठता अंतर्निहित होती है।

26. निर्वासन को उचित ठहराने वाली सामग्री प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों पर भी प्रकाश डाल सकती है। यदि सामग्रियों का संदर्भ दिया जाता है, तो निष्कासन का निर्देश देने वाला प्राधिकारी उस विकल्प को भी इंगित करता है जिसे वह उचित और उपयुक्त मानता है, इसे ख़राब नहीं कहा जा सकता है, भले ही अन्य विकल्पों का कोई विशिष्ट संदर्भ न हो। यह वैध निष्कर्ष का विषय है कि जब निष्कासन की वांछनीयता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सामग्री पर विचार किया जाता है, तो विकल्पों पर भी विचार किया जाता है और तीन विकल्पों में से एक को अपनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे मामलों से निपटने के दौरान जोड़ों में थोड़ा सा खेल निश्चित रूप से स्वीकार्य है।

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर प्रतिवादी की ओर से उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट या अनिर्दिष्ट था, जिसमें कहा गया था:

... उनमें याचिकाकर्ता के खिलाफ भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति शामिल है। उन मामलों का विवरण सूचीबद्ध किया गया है जिनमें वह शामिल था और उस पर व्यक्ति और संपत्ति के लिए खतरा होने का एक सामान्य आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों के मर्म को समझा और उनका उचित जवाब दिया।इनके आलोक में, मेरी राय है कि कारण बताओ नोटिस में वर्णित आरोप और आधार अस्पष्ट या विकृत नहीं हैं।

हालाँकि, ऐसा मानते हुए, विद्वान न्यायाधीश इस मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़े कि क्या बाहरी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई सबूत मौजूद है या नहीं। यह भीम सिंह बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य मामले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फै सले पर निर्भर था, 2002 (2) जेसीसी 1132 और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक मामलों के संबंध में कारण बताओ नोटिस में उन गवाहों के नाम बताए गए हैं जिनके बारे में कहा गया था कि वे प्रतिवादी के खिलाफ गवाही देने के लिए अनिच्छुक थे या आगे नहीं आए थे। भय के कारण खुलासा नहीं किया गया तो प्राकृतिक न्याय के

सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। आगे यह माना गया कि अधिकारियों ने यह कहते हुए अपना दिमाग नहीं लगाया:

... अधिनियम की धारा 47 के तहत राय निर्माण में वस्तुनिष्ठ सामग्री की यह न्यूनतम आवश्यकता, साथ ही उस पर दिमाग का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि इशाक में निर्णय से पता चलता है, रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से संतुष्टि का सुझाव या समर्थन करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि किन मामलों में गवाहों ने अपनी सुरक्षा की आशंका के कारण उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। निस्संदेह, दोनों कारण बताओ नोटिस में मामलों की एक सूची दिखाई देती है। हालाँकि, नोटिस में यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इनमें से किस मामले में याचिकाकर्ता की गतिविधियों के कारण गवाह सामने नहीं आ रहे थे...

क्षेत्र में लागू होने वाला कानून अब एकीकृत नहीं रह गया है जिस पर इसके बाद ध्यान दिया जा सकता है:

(i) अधिनियम के तहत कार्यवाही में सभी वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) तात्पर्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कासन की कार्यवाही को निवारक निरोध मामले के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

(iii) निर्वासन का आदेश पारित होने से पहले, कार्यवाही प्राप्तकर्ता सुनवाई के अवसर का हकदार है।

(iv) अधिनियम में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का परीक्षण ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

(v) प्राधिकारी की संतुष्टि वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

(vi) दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 47 के तहत एक कार्यवाही इस अर्थ में सामान्य कार्यवाही से अलग स्तर पर है, जबकि बाद में साक्ष्य के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है और इस प्रकार, एक अवसर मिलता है उनसे निपटने के लिए आगे बढ़ें, पूर्व में, सामान्य आरोप उद्देश्य की पूर्ति करेंगे।

उच्च न्यायालय को आम तौर पर अपनी पहचान गुप्त रखने के इरादे को व्यक्त करने के लिए गवाहों के बयान सहित संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने पर जोर देना चाहिए ताकि इस बात पर संतुष्टि हो सके कि ऐसे बयान पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और पुलिस द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं।

हमने यहां पहले देखा है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं माना था कि नोटिस में लगाए गए आरोप वैधानिक आवश्यकता को पूरा करते हैं, लेकिन हमारी राय में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही नहीं था कि तीसरा अपीलकर्ता खुलासा करने के लिए बाध्य था। ऐसे मामले जिनमें गवाहों ने डर के कारण या धमकी आदि के कारण प्रतिवादी के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। यदि उन मामलों को संप्रेषित करने का प्रयास किया

जाता है जिनमें गवाह कार्यवाहीकर्ता की गतिविधियों के कारण सामने नहीं आ रहे थे, तो यह गोपनीयता का उल्लंघन होगा। बनाए रखने की आवश्यकता है और अन्यथा यह उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए अधिनियम की धारा 47 अधिनियमित की गई थी।

निर्वासन का आदेश हमेशा बाहरी व्यक्ति की अवैध गतिविधियों के क्षेत्र तक ही सीमित होना चाहिए। कार्यकारी आदेश को वैधानिक प्राधिकारी की ओर से उचित विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। जब किसी आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, तो वह सामग्री देखी जाएगी जिस पर प्राधिकारी की संतुष्टि आधारित है। प्राधिकारी की संतुष्टि हालांकि मुख्य रूप से व्यक्तिपरक है, लेकिन वस्तुनिष्ठता पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन सामग्री की पर्याप्तता पर रिट अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में प्राधिकरण प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा है या इसलिए अप्रासंगिक कारकों पर अपना निर्णय आधारित किया है। किसी अन्य दृष्टिकोण की संभावना मात्र हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती। यह ऐसा मामला नहीं है जहां तीसरे अपीलकर्ता के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया था।

उच्च न्यायालय और यह न्यायालय निस्संदेह एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

अदालतें कार्यवाही करने वाले व्यक्ति के मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करेंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की निस्संदेह रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन किसी क़ानून के मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या करते समय और क्षेत्र में चल रहे उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, अदालत स्वयं रिकॉर्ड की जांच कर सकती है ताकि न केवल इस उद्देश्य के लिए अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके कि कार्यवाही करने वाले के लिए उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान किया गया है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए भी कि गवाहों ने कार्यवाहीकर्ता की गतिविधियों के कारण अदालत में सच्चाई और निडरता से गवाही देने के बारे में अपनी आशंकाओं का खुलासा किया है। एक बार इस तरह की संतुष्टि हो जाने पर, उच्च न्यायालय आम तौर पर निर्वासन के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत, किसी भी स्थिति में, अधिकारियों को गवाहों के नाम या उन मामलों की संख्या का खुलासा करने का निर्देश नहीं देगी जहां ऐसे गवाहों से के वल इस कारण से पूछताछ की गई थी कि इससे उन् हें और अधिक नुकसान हो सकता है। किसी दिए गए मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है और उक्त मामले में आरोपी के रूप में कार्यवाही करने वाले से यह जानने की उम्मीद की जाती है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहों की जांच की गई थी, वे कौन थे और इस प्रकार, इसे बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? ऐसे व्यक्तियों की पहचान के संबंध में गोपनीयता

समाप्त हो सकती है। अदालत को खुद को याद दिलाना चाहिए कि कानून महज तर्क नहीं है बल्कि उसे अपने अनुभव के आधार पर लागू करना जरूरी है।

उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों के समर्थन में इस न्यायालय के एक फै सले पर मजबूत भरोसा जताया है गाजी सदुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2003] 7 एससीसी 330, जिसमें इस न्यायालय ने कहा:

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हमें तथ्यों के आधार पर मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि अपीलकर्ता के वकील ने जिद जारी रखी और रिकॉर्ड पर मौजूद तीन गवाहों के बयान सहित पूरे साक्ष्य के माध्यम से हमें ले लिया। पुलिस कै मरे के सामने, हम तथ्यों पर अपने निष्कर्ष भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीन गवाहों के बयानों पर गौर करने से पता चलता है कि उन्होंने गवाहों को उनके द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। गवाहों द्वारा यह कहा गया है कि अपीलकर्ता इलाके में गरीब व्यक्तियों को धमकी देता था और मारपीट करता था और इलाके में आतंक पैदा कर रखा था। अपीलकर्ता निवासियों को सांप्रदायिक आधार पर भड़का रहा था और उनके बीच वैमनस्य पैदा कर रहा था। वह आम जनता को परेशान कर रहा था और इलाके की

सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को परेशान कर रहा था। अपीलकर्ता ने दो गवाहों को पीटा था और चाकू की नोक पर उनसे क्रमशः 700 और 300 रुपये छीन लिए थे। तीसरे गवाह ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता को लोगों को पीटने और धमकी देने की आदत थी, जिसके परिणामस्वरूप मंजूरपुरा, हर्ष नगर और लोटा कारंजा क्षेत्रों के निवासियों के मन में आतंक पैदा हो गया था। कि वह सांप्रदायिक था और समुदायों के बीच नफरत फैला रहा था। उसका यह भी कहना था कि उसने उसे पीटा था और धमकी दी थी कि यदि उसने हिंदू समुदाय को सबक सिखाने में उसकी मदद नहीं की तो वह उसे जान नहीं देगा।

यह आगे आयोजित किया गया था:

... प्राथमिक रूप से, संतुष्टि आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की होनी चाहिए। यदि प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि वस्तुनिष्ठ है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित है तो अदालतें प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में के वल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि संभवतः कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी की ऐसी संतुष्टि में के वल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब दर्ज की गई संतुष्टि या तो सबूतों के अभाव, सबूतों की गलत व्याख्या के आधार पर प्रदर्शनात्मक रूप से विकृत हो या जिसे कोई उचित व्यक्ति नहीं बना सका या संबंधित व्यक्ति

को उचित अवसर नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

यहां तक कि संजीव उर्फ बिट्टू (सुप्रा) में भी यह देखा गया:

"धारा 47 में दो भाग हैं। पहला भाग पुलिस आयुक्त या किसी अधिकृत अधिकारी की इस निष्कर्ष पर पहुंचने की संतुष्टि से संबंधित है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों या कृ त्यों से व्यक्ति या संपत्ति को खतरा और खतरा पैदा हो रहा है या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा व्यक्ति संलिप्त है या इसके बारे में है। प्रगणित अपराधों को अंजाम देने में या ऐसे किसी अपराध को बढ़ावा देने में संलग्न होना या इतना हताश और खतरनाक है कि उसका अस्तित्व बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए खतरनाक हो गया है। संबंधित अधिकारी की यह राय बननी होगी कि गवाह व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में अपनी ओर से आशंका के कारण ऐसेव्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए सार्वजनिक रूप से आगे आने को तैयार नहीं हैं। आधार बनाने वाली सामग्रियों के आधार पर ये राय बनने के बाद आयुक्त प्रावधान में दिए गए किसी भी उपलब्ध विकल्प को अपनाते हुए आदेश पारित कर सकता है। तीन विकल्प हैं:

(1) ऐसे व्यक्ति को हिंसा और भय को रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आचरण करने का निर्देश देना या (2) उसे खुद को दिल्ली के किसी भी हिस्से से बाहर निकालने का निर्देश देना या (3) खुद को दिल्ली के बाहर हटाने का निर्देश देना। पूरी दिल्ली यद्यपि हमारे लिए कानून को सटीक शब्दों में निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर उनकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना है, हमने कानून के व्यापक प्रस्तावों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अपनी असहमति दर्ज करेंगे। निर्वासन की अवधि समाप्त हो चुकी है। मामले को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को प्रभावी करने की आवश्यकता नहीं है।"

उपरोक्त कारणों से, इस अपील को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ स्वीकार किया जाता है और इसका निपटारा किया जाता है। कोस्ट के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वीनस चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।